Drishti IAS

करेंट अफेयर्स बिहार

दिसंबर (संग्रह)

2022

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

बिहार **3**

- बिहार के 25 ज़िलों में लागू होगा ग्रेडेड एक्शन प्लान 3
- पटना की कृति ने कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जीते छह स्वर्ण पदक 3
- पटना, पूर्णिया और दरभंगा में खतरनाक स्तर पर पहुँचा प्रदूषण 4
- बिहार के धर्मेंद्र सिंह ने 1 मिनट में सिर से फोड़े 21 बेल, बनाया 7वाँ विश्व रिकॉर्ड 4
- एशियन अंडर-19 रग्बी चैंपियनशिप के लिये बिहार के चार बालिका और चार बालक खिलाड़ियों का हुआ चयन 4
- बिहार के जहानाबाद के वाणावर में रोपवे का निर्माण शुरू 5
- महाराष्ट्र व तमिलनाडु के तर्ज पर गया में विकसित होगा टेक्सटाइल पार्क 5
- अकबरनगर में बनेगा कार्गो टर्मिनल 6
- बीपीएससी ने पहली बार जारी किया मुख्य परीक्षा के प्रश्न का फॉर्मेट 6
- गया मगध मेडिकल अस्पताल में बनेगा 50 बेडों का क्रिटिकल केयर यूनिट 7
- बिहार के 15 विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय ऑनलाइन होंगे लिंक 7
- बीपीएससी और बीटीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतम पाँच बार बैठ सकेंगे सरकारी सेवक 7
- बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) मॉडल उपविधि 2022 की स्वीकृति 8
- बिहार उद्योग विभाग ने पहली बार औद्योगिक विकास की रैंकिंग जारी की 9
- देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में पाँचों बिहार के 9
- पटना में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने का काम शुरू 9
- बिहार नगर पालिका विधेयक, 2022 पारित 10
- बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब 611 प्रकार की दवाएँ मुफ्त में मिलेगी, बिहार सरकार ने जारी की गाइड लाइन 10
- पटना में मनाया जाएगा 13वाँ फिल्मोत्सव 11
- बिहार का हरित बजट पिछले साल की तुलना में 3.26 फीसदी हुआ कम 11
- बिहार को मिलेगी एक नए एक्सप्रेस-वे की सौगात, 2023 में शुरू होगा रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस-वे का निर्माण 12
- स्वच्छता सर्वे 2023 के तहत ब्रांडिंग में प्लास्टिक का बैनर-पोस्टर लगाने पर कटेंगे 25 अंक 12
- बागमती बांध के किनारे बनेगा बेनीपुरी का स्मारक 13
- बिहार की शालिनी कुमारी को तीसरे आसियान-भारत ग्रासरूट इनोवेशन फोरम में उनके नवाचार 'मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग्स' के लिये मिला प्रथम पुरस्कार 13
- बिहार में शिक्षक नियोजन के नियमों में होगा बड़ा बदलाव 14
- बिहार के 16 शहरों में 1136 करोड़ की लागत से एसटीपी व ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाएंगे 15
- बिहार की कोसी-मेची लिंक परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ 15
- 'नमामि गंगे' में अब भूगर्भ जल को भी साफ करने की योजना 16
- कैमूर में खुलेगा वाटर स्पोर्ट्स सेंटर 16
- डॉ. रत्नेश्वर मिश्र को मिलेगा साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 17

नोट :

बिहार

बिहार के 25 ज़िलों में लागू होगा ग्रेडेड एक्शन प्लान

चर्चा में क्यों ?

28 नवंबर, 2022 को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष प्रो. अशोक घोष ने पटना के परिवेश भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि परिषद ने एक ग्रेडेड एक्शन प्लान तैयार किया है, जो छह माह बाद राज्य के उन सभी 25 ज़िलों में लागू होगा, जहाँ एयर क्वालिटी नापने के लिये बीते दिनों नये मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- राज्य में ग्रेडेड एक्शन प्लान के अंतर्गत 100 से अधिक एक्यूआई वाले प्रदूषित शहरों में प्रदूषण फैलाने पर रोक होगी।
- यह रोक प्रदूषण स्तर (एक्यूआई) की गंभीरता के अनुसार अलग-अलग शहरों में अलग-अलग तरह की होगी। इसके क्रियान्वयन का जिम्मा संबंधित ज़िलों के डीएम और संबंधित विभागों पर होगा।
- विदित है कि पर्यावरण संबंधी पहले से बने कानून के अनुसार इस तरह के एक्शन प्लान को लागू करने के लिये एक वर्ष का आँकड़ा होना जरूरी है। इसलिये ग्रेडेड एक्शन प्लान तैयार होने के बावजूद इसे लागू नहीं किया गया है।
- राज्य के 22 ज़िलो में नवस्थापित 25 मॉनीटरिंग स्टेशनों की स्थापना के लगभग छह महीने हो चुके हैं और अगले छह महीने बाद इसके एक वर्ष पूरे हो जाने के बाद ग्रेडेड एक्शन प्लान को लागू कर दिया जाएगा।
- प्रो. अशोक घोष ने बताया कि राज्य में 450 से अधिक एक्यूआई होने पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा वायु प्रदूषण स्वास्थ्य इमरजेंसी घोषित किया जाएगा। राष्ट्रीय वायु शुद्धता कार्यक्रम के अंतर्गत डीएम के नेतृत्व में ज़िला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया जाएगा, जो स्कूलों को बंद करने समेत अन्य अतिरिक्त कदम उठाने पर निर्णय लेगा।

पटना की कृति ने कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जीते छह स्वर्ण पदक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बिहार के पटना जिले की कृति राज सिंह ने न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छह स्वर्ण पदक जीतकर बिहार व देश का नाम रोशन किया है।

प्रमुख बिंदु

- कृति ने अंडर 18 के 57 किग्रा. भार वर्ग के तीन इवेंट में जीत का परचम लहराया। कृति ने रो बैंड प्रेस और इक्यूप्ट बेंच प्रेस में एक-एक स्वर्ण और होल पावर लिफ्टिंग में 95 किग्रा. भार उठाकर चार स्वर्ण पदकों पर कब्जा जमाया।
- इससे पहले जुलाई में हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में कृति ने तीन काँस्य पदक जीते थे।
- पटना ज़िले के खुसरूपुर प्रखंड के बड़ा हसनपुर गाँव की रहने वाली कृति राज सिंह गुवाहाटी के रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन कॉलेज से फिजिकल एजुकेशन फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। उसके पिता ललन सिंह यादव साधारण किसान हैं।
- कृति राज ने बताया कि वह स्कूल के समय से ही खेल में रुचि लेने लगी थी। उसने आगे बढ़ने के लिये कई बड़े नेताओं से मदद मांगी लेकिन सभी जगह केवल आश्वासन ही मिला। आईपीएस पंकज राज ने उसे एक लाख रुपए की मदद की।

नोट :

पटना, पूर्णिया और दरभंगा में खतरनाक स्तर पर पहुँचा प्रदूषण

चर्चा में क्यों ?

4 दिसंबर, 2022 को जारी आँकड़ों के मुताबिक बिहार के पूर्णिया, दरभंगा और राजधानी पटना में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है। पूर्णिया और दरभंगा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुँच चुका है। वहीं राजधानी पटना में एक्यूआई 378 है।

प्रमुख बिंदु

- 4 दिसंबर शाम चार बजे तक के आँकड़ों के मुताबिक पूर्णिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स 423 और दरंभगा में 422 पहुँच गया था। वायु प्रदूषण का यह खतरनाक स्तर मानव स्वास्थ्य के लिये बेहद हानिकारक माना जाता है।
- बिहार के लगभग सभी शहरों में प्रदूषण का कारण पीएम 5 है। पीएम 2.5 हवा में मौजूद ऐसे धूल कणों को कहा जाता है जिनका आकार 2.5 माइक्रोन से कम होता है। यह साँस के ज़रिये शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाते हैं।
- इसके साथ ही बिहार के अन्य सभी प्रमुख शहरों में प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब है। आँकड़ों के मुताबिक जिन शहरों की हवा बेहद खराब है, उनमें औरंगाबाद का एक्यूआई 342, बेतिया का एक्यूआई 354, भागलपुर का एक्यूआई 335, बिहार शरीफ का एक्यूआई 368, गया का एक्यूआई 313, कटिहार का एक्यूआई 391, मुंगेर का एक्यूआई 301, राजगीर का एक्यूआई 360, सहरसा का एक्यूआई 362, समस्तीपुर का एक्यूआई 345, सासाराम का एक्यूआई 329 रहा।

बिहार के धर्मेंद्र सिंह ने 1 मिनट में सिर से फोड़े 21 बेल, बनाया 7वाँ विश्व रिकॉर्ड

चर्चा में क्यों ?

5 दिसंबर, 2022 को नेताजी वर्ल्ड रिकॉर्ड फाउंडेशन द्वारा आयोजित सिर से कच्चे बेल फोड़ने की ऑनलाइन प्रतियोगिता में बिहार के धर्मेंद्र सिंह ने 1 मिनट में सिर से 21 कच्चे बेल फोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया।

प्रमुख बिंदु

- नेताजी वर्ल्ड रिकॉर्ड फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 32 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पर चीन के खिलाड़ी ने 17 बेल फोड़े और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के खिलाड़ी ने 15 बेल फोड़े।
- इंडिया के हैमर हेड मैन की उपाधि से सम्मानित धर्मेंद्र सिंह कैमुर ज़िले के रामगढ़ के रहने वाले हैं। वह वर्तमान में त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के जवान हैं।
- उल्लेखनीय है कि धर्मेंद्र सिंह ने पहले से 6 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किये थे, जिसमें सिर से नारियल तोड़ने, कच्चे बेल तोड़ने, दाँत से सरिया मोड़ने, सिर से सरिया मोड़ने, स्किपिंग, बैक साइड से सरिया मोड़ने जैसी प्रतियोगिताएँ शामिल हैं। धर्मेंद्र सिंह का नाम गिनीज बुक में भी दर्ज है।

एशियन अंडर-19 रग्बी चैंपियनशिप के लिये बिहार के चार बालिका और चार बालक खिलाड़ियों का हुआ चयन

चर्चा में क्यों ?

6 दिसंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार नेपाल के काठमांडू में 10-11 दिसंबर 2022 को आयोजित होने वाले एशियन अंडर-19 रग्बी चैंपियनशिप के लिये भारतीय रग्बी टीम की घोषणा कर दी गई है। इस टीम में बिहार के चार बालिका और चार बालक खिलाड़ियों का चयन हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय टीम का प्रशिक्षण शिविर पुणे के बालेबाड़ी स्टेडियम में आठ नवंबर से छह दिसंबर तक लगा हुआ था, इस प्रशिक्षण शिविर में पूरे भारत से 30 बालक और 30 बालिका खिलाड़ी शामिल हुए थे।

नोट :

- भारतीय रग्बी टीम में बिहार से बालिका वर्ग में आरती कुमारी, सपना कुमारी, धर्मशिला कुमारी और अर्चना कुमारी का चयन हुआ है तथा बालक वर्ग में अरमान आलम, हर्ष राज, सौरभ कुमार और राजू कुमार का चयन हुआ है।
- इसके अलावा अरमान आलम को अंडर-19 भारतीय रग्बी टीम का कप्तान भी बनाया गया है, जो बिहार के लिये एक बड़ी उपलब्धि है।
- विदित है कि नेपाल में आयोजित हो रही इस चैंपियनशिप में दुनिया के 10 देश हिस्सा ले रहे हैं।

बिहार के जहानाबाद के वाणावर में रोपवे का निर्माण शुरू

चर्चा में क्यों ?

7 दिसंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के जहानाबाद ज़िले के ऐतिहासिक 'मगध का हिमालय'नाम से मशहूर मखदुमपुर प्रखंड के वाणावर पहाड़ पर लंबे अरसे के बाद रोपवे निर्माण का कार्य शुरू हो गया है।

प्रमुख बिंदु

- जहानाबाद ज़िले के इस पहाड़ी इलाके के हथियाबोर में निर्माण कंपनी के द्वारा कैंप कार्यालय खोला गया है तथा पहाड़ी इलाके में लगे जंगल की सफाई भी की गई है।
- रोपवे के निर्माण का कार्य बिहार राज्य पुल निगम ने बंगाल की कंपनी दामोदर रोपवे निर्माण लिमिटेड को सौंपा है। पहाड़ी इलाके में निर्माण कंपनी के मज़दूर पहाड़ के चिह्नित स्थानों पर पत्थरों को तोड़कर ड्रिल मशीन के सहयोग से पत्थर में पीलिंग का कार्य कर रहे हैं।
- ज्ञातव्य है कि वाणावर पहाड़ पर रोपवे निर्माण के लिये राज्य के मखदुमपुर के पूर्व विधायक सह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने 16 नवंबर, 2016 को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति प्रदान की थी।
- हालाँकि कुछ माह पूर्व वन विभाग ने भी रोपवे निर्माण के लिये अपनी मंज़ूरी एवं एनओसी दे दिया है, जिसके बाद दामोदर रोपवे कंपनी के द्वारा कार्य शुरू किया गया।
- वाणावर पहाड़ में रोपवे निर्माण दो इलाकों से कराया जाएगा। प्रथम फेज में हथियाबोर एवं दूसरे फेज में पाताल गंगा से कार्य कराया जाएगा।

महाराष्ट्र व तमिलनाडु के तर्ज पर गया में विकसित होगा टेक्सटाइल पार्क

चर्चा में क्यों ?

7 दिसंबर, 2022 को बिहार के गया ज़िले के डीएम डॉ. त्यागराजन ने बताया कि गया में मानपुर के शादीपुर बालू घाट के समीप महाराष्ट्र व तमिलनाडु के तर्ज पर टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा। इस पार्क के लिये चिह्नित लगभग 23 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस पार्क के बनने के बाद फल्गु नदी को प्रदूषणमुक्त रखने व लोगों को रोज़गार के लिये सुनहरा अवसर मिलेगा। वर्तमान में कपड़ा रँगाई का रंगीन पानी नदी में ही गिराया जाता है, जिसको लेकर कई बार शिकायत की गई है।
- डीएम डॉ. त्यागराजन ने बताया इस पार्क के निर्माण में अत्याधुनिक 435 यूनिट लगाने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें कोट, पैंट सहित नये प्रकार के अत्याधुनिक कपड़ों का निर्माण किया जाएगा। टेक्सटाइल पार्क निर्माण होने से लोकल स्तर के साथ-साथ ज़िला स्तर पर अधिक संख्या में रोज़गार मिलेगा, जिससे यह क्षेत्र भविष्य में काफी विकसित हो जाएगा।
- उन्होंने बुनकर सेवा समिति के अध्यक्ष को बताया कि विभिन्न बैंकों के साथ बैठक कर वस्त्र उद्योग व अत्याधुनिक मशीन खरीदने के लिये ऋण वितरण में सहयोग देने को लेकर हर संभव प्रयास किये जाएंगे।
- वस्त्र उद्योग बुनकर सेवा समिति के अध्यक्ष प्रेम नारायण पटवा ने टेक्सटाइल पार्क के बारे में बताया कि वर्तमान में पटवाटोली में अपने घरों में 980 यूनिट, जो लगभग 12500 पावर लूम मशीन से कपड़ा बुनाई का काम कर रहे हैं, इसमें लगभग 30 से 35 हज़ार कामगार व श्रमिक काम करते हैं। इसके अलावा इसमें लगभग 50 प्रतिशत महिला कामगार हैं।

नोट :

अकबरनगर में बनेगा कार्गो टर्मिनल

चर्चा में क्यों ?

7 दिसंबर, 2022 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बिहार के भागलपुर के अकबरनगर में कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि अकबरनगर में बनने वाले कार्गो टर्मिनल को मालदा मंडल रेल प्रबंधक विकास चौबे के नेतृत्व में बनाया जाएगा, जिसे वर्ष 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है।
- विदित है कि पूर्व रेलवे के मालदा मंडल में एक ऐसा ही टर्मिनल गोड्डा में चालू किया गया है।
- रेल मंत्री ने बताया कि भारतीय रेलवे अगले तीन वर्षों में दर्जनों कार्गो टर्मिनल की स्थापना करेगा। 22 कार्गो टर्मिनल पहले ही शुरू किये जा चुके हैं, जबकि ऐसे टर्मिनलों के विकास के लिये 125 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 79 को सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है।
- रेलवे ने प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिये भारतीय खाद्य निगम के लिये टर्मिनल के निर्माण हेतु बिहार लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड को सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी है।
- इस कार्गो टर्मिनल में साइलो टाइप कंटेनरों का उपयोग किया जाएगा। साइलो को मूल रूप से अनाज और अन्य सामग्री को स्टोर करने के लिये डिजाइन किया गया है। भारत में इस प्रकार के भंडारण का प्रयोग कम ही होता है।

बीपीएससी ने पहली बार जारी किया मुख्य परीक्षा के प्रश्न का फॉर्मेट

चर्चा में क्यों ?

9 दिसंबर, 2022 को बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने 67वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का पहली बार फॉर्मेट जारी किया है। इसमें सिविल इंजीनियरिंग और मानवशास्त्र छोड़ अन्य सभी विषयों के फॉर्मेट एक होंगे। इनमें सिलेबस के अलग-अलग भागों पर आधारित छह प्रश्न आएंगे, जिनमें पहला व चौथा प्रश्न लघु-उत्तरीय होगा।

प्रमुख बिंदु

- पहले प्रश्न के सभी प्रश्न सेक्शन एक से होंगे, जबकि चौथे प्रश्न के सभी लघु-उत्तरीय प्रश्न सेक्शन दो से होंगे। प्रश्न संख्या दो और तीन वर्णात्मक होंगे, जिनमें हर प्रश्न के विकल्प के रूप में एक प्रश्न होगा। इनमें दोनों प्रश्न विकल्प समेत सेक्शन एक से होंगे। प्रश्न पाँच और छह के दो-दो विकल्प होंगे। ये दोनों प्रश्न विकल्प समेत सेक्शन दो से होंगे और इनमें से प्रत्येक का उत्तर देना होगा।
- मानवशास्त्र में सिलेबस के तीन पार्ट हैं। इनमें सेक्शन एक से दो प्रश्न होंगे। इनमें पहले प्रश्न में लघु-उत्तरीय प्रश्न होंगे और यह सेक्शन एक के पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या दो वर्णनात्मक प्रकृति का होगा और इसका एक-एक विकल्प भी दिया होगा। विकल्प समेत यह प्रश्न सिलेबस के सेक्शन एक से ही होगा।
- सेक्शन दो के दो उपभाग ए और बी होंगे। इनमें दोनों में दो-दो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे और दोनों के विकल्प भी होंगे। ये सभी प्रश्न सेक्शन दो के सिलेबस पर आधारित होंगे और इनमें किसी एक उपभाग के दोनों प्रश्नों का उत्तर देना होगा।
- सेक्शन तीन में दो प्रश्न होंगे, जिनमें से पहला प्रश्न लघु-उत्तरीय होगा और इसमें सेक्शन तीन के पूरे सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा प्रश्न वर्णनात्मक होगा और इसका विकल्प भी दिया होगा। विकल्प समेत यह प्रश्न सेक्शन तीन के सिलेबस से होगा। अभ्यर्थियों को दोनों प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।
- सिविल इंजीनयरिंग का पहला प्रश्न लघु-उत्तरीय होगा, जो सेक्शन एक के पूरे सिलेबस से पूछा जाएगा। सेक्शन एक के पार्ट ए, बी और सी से विकल्प समेत तीन प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं दो का अभ्यर्थियों को उत्तर देना होगा। प्रश्न संख्या पाँच जो सेक्शन दो का पहला प्रश्न होगा लघु-उत्तरीय होगा और इसके चार पार्ट होंगे। इनमें से किन्हीं दो पार्ट का उत्तर देना होगा।
- सेक्शन दो के सिलेबस के पार्ट ए, बी, सी, डी पर आधारित विकल्प समेत चार वर्णनात्मक प्रश्न भी होंगे जिनमें से दो का अभ्यर्थियों को उत्तर देना होगा।

नोट :

गया मगध मेडिकल अस्पताल में बनेगा 50 बेडों का क्रिटिकल केयर यूनिट

चर्चा में क्यों ?

9 दिसंबर, 2022 को गया के मगध मेडिकल अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डॉ. एन के पासवान ने बताया कि अस्पताल परिसर में क्रिटिकल केयर यूनिट बनाने का प्रस्ताव है। इसमें हृदय रोग, साँस, हेड इंजरी, शरीरिक चोट, सर्जरी सहित अन्य बीमारियों के गंभीर मरीजों का इलाज हो सकेगा।

प्रमुख बिंदु

- प्रभारी अधीक्षक ने बताया कि यूनिट के निर्माण में 70 फीसदी अंशदान केंद्र सरकार और शेष 30 फीसदी प्रदेश सरकार देगी।
- यह यूनिट अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित होगा। यूनिट में पोर्टेबल एक्स-रे मशीन, पोर्टेबल सोनोग्राफी, एडवांस इक्विपमेंट सहित अन्य सुविधाएँ होंगी।
- गौरतलब है कि मगध मेडिकल अस्पताल में अब तक क्रिटिकल मरीजों को रेफर करने पर ही ज़ोर दिया जाता था। इनमें सबसे अधिक एक्सीडेंटल व बर्न के मरीज शामिल होते हैं। अस्पताल में हृदय रोग विभाग न होने के कारण इससे संबंधित मरीज इलाज के लिये यहाँ कम ही पहुँचते हैं।

बिहार के 15 विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय ऑनलाइन होंगे लिंक

चर्चा में क्यों ?

11 दिसंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के सभी 15 पारंपरिक विश्वविद्यालयों के सभी पुस्तकालयों को ऑनलाइन जोड़ने के लिये शिक्षा विभाग, यूजीसी - इन्फ्लिबनेट के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- इस एमओयू में शिक्षा विभाग के अलावा सभी 15 विश्वविद्यालयों के कुलपति/कुलसचिव और यूजीसी-इन्फिलबनेट के निदेशक शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में एक समारोह में एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे।
- आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस एमओयू के जरिये प्रत्येक विश्वविद्यालय को ऑनलाइन पता होगा कि कौन -सी किताब किस विश्वविद्यालय में है। अगर वह किताब डिजिटाइज फॉर्म में नहीं है, तो उस किताब को हासिल करने के लिये खुद विश्वविद्यालय दूसरे विश्वविद्यालय से लेकर किताब उपलब्ध कराएगा। इस पर लगने वाला आर्थिक भार खुद विश्वविद्यालय वहन करेगा।
- इस नई व्यवस्था के तहत किताबों का कैटलॉग बनेगा। विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को इस सुविधा के लिये अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देना होगा। इस तरह प्रदेश के विश्वविद्यालयों के रिसर्च स्कॉलर और शिक्षकों को इंटर लाइब्रेरी लोन की सौगात जल्दी ही मिलेगी।
- यह समूची कवायद यूजीसी गाइडलाइन पर की जाएगी। इसके लिये विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों का स्वचालन सिस्टम बनाया जाएगा, जिसमें किताबों के बारकोड आदि भी दिये जाएंगे। इसके अलावा शोध गंगा, शोध चक्र, इ-शोध सिंधु और शोध शुद्धि सिस्टम प्रभावी किये जाएंगे।

बीपीएससी और बीटीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतम पाँच बार बैठ सकेंगे सरकारी सेवक

चर्चा में क्यों ?

12 दिसंबर, 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के सरकारी सेवक अपनी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में अब अधिकतम पाँच बार भाग ले सकेंगे।

प्रमुख बिंदु

- कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. सिद्धार्थ ने प्रेस वार्ता में बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिये अवसरों की सीमा की स्वीकृति दी गई है।

नोट :

- कैबिनेट के निर्णय के अनुसार बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में प्रत्येक आयोग (बीपीएससी, बीटीएससी, बीएसएससी) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिये अलग-अलग अधिकतम कुल 5 (पाँच) अवसर ही अनुमन्य होंगे।
- निर्धारित 5 अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारंभ होगी। पूर्व में उपभोग कर लिये गए अवसरों की एतदर्थ उपेक्षा की जाएगी।
- बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने के लिये नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट पूर्ववत् अनुमन्य होगी परंतु उक्त आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तब तक अधिकतम 5 अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो।
- गौरतलब है कि इससे पहले राज्य के सरकारी सेवकों को अधिकतम तीन बार तक प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने का प्रावधान था।

बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) मॉडल उपविधि 2022 की स्वीकृति

चर्चा में क्यों ?

12 दिसंबर, 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) मॉडल उपविधि 2022 को स्वीकृति दी गई। इसके तहत पहली बार सरकार ने सिंगल यूज्ड पॉलिथीन का उपयोग करने वालों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है।

प्रमुख बिंदु

- कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सिचवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने प्रेस वार्ता में बताया कि बिहार में अब सिंगल यूज्ड पॉलिथीन और उससे बनी वस्तुओं का उपयोग करने वालों को जुर्माना देना होगा। इसका निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण व बिक्री करने वालों पर भी जुर्माने की राशि तय कर दी गई है।
- प्रावधान के मुताबिक स्थानीय निकाय को बिना सूचना दिये और इस बाइलॉज के अनुसार व्यवस्था किये बिना कोई भी खेल और सभा आयोजित करना और इसमें सिंगल यूज्ड पॉलिथीन का उपयोग किया जाना भी गैरकानूनी होगा।
- 100 से अधिक व्यक्तियों को जमा करने पर जिम्मेदार आयोजक पर पहली बार 1500 रुपए दूसरी बार दो हज़ार रुपए और उसके बाद हर बार 2500 रुपए का जुर्माना देना होगा। एक से अधिक आयोजक होने पर उन सभी को अलग-अलग जुर्माना राशि देनी होगी।
- अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सिंगल यूज वाले पॉलिथीन और इससे बनी वस्तुओं में इयर बड्स की प्लास्टिक की डंडिया, गुब्बारों की प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की डंडिया, आइइसक्रीम की डंडिया, सजावट के लिये पॉलिस्टाइरिन (थर्मोकोल) से बने समान, कप, प्लेट, गिलास, कटलरी के सामान जैसे काँटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, स्ट्रिर, साथ ही मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट के इर्द गिर्द लपेटने या पैक करनेवाली प्लास्टिक की फिल्में और 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी के बैनर शामिल हैं।
- नगर निकायों के अधिकारिता क्षेत्र में इयर बड, झंडे, कैंडी स्टिक, प्लेट कप, काँटा-चम्मच जैसी सामग्रियों का उपयोग करने वालों पर पहली बार दो हज़ार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा, दूसरी बार इनके उपयोग या बेचनेवाले को तीन हज़ार रुपए और उसके बाद हर बार दोहराए जाने पर पाँच हज़ार रुपए की दर से जुर्माना वसूला जाएगा। इसी प्रकार से इन सामग्रियों की कॉमर्शियल उपयोगकर्त्ताओं पर पहली बार 1500 रुपए, दूसरी बीर 2500 रुपए और उससे अधिक बार उपयोग करने पर 3500 रुपए प्रत्येक बार जुर्माना लिया जाएगा।
- इसके अलावा मल्टी लेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक सीट या ऐसी ही वस्तु के शीट से बने कवर जो प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधनों के अनुसार निर्मित लेबल या मार्क नहीं किये गए हैं, के उपयोग करने पर पहली बार दो हज़ार, दूसरी बार तीन हज़ार और उससे अधिक होने पर हर बार पाँच हज़ार रुपए का जुर्माना लिया जाएगा।
- प्लास्टिक को खुले में जलाने पर पहली बार दो हज़ार रुपए, दूसरी बार तीन हज़ार रुपए और उसके बाद प्रति बार पाँच हज़ार रुपए का जुर्माना लिया जाएगा।
- सार्वजनिक स्थलों, पार्क, नाला, पुरातात्त्विक स्थलों और अन्य प्रतिबंधित स्थलों पर प्लास्टिक कचरा फैलाने पर पहली बार एक हज़ार रुपए, दूसरी बार 1500 रुपए और उसके बाद हर बार दो हज़ार रुपए का जुर्माना देना होगा।

नोट :

बिहार उद्योग विभाग ने पहली बार औद्योगिक विकास की रैंकिंग जारी की

चर्चा में क्यों ?

13 दिसंबर, 2022 को बिहार उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंडरीक ने बताया कि राज्य उद्योग विभाग ने पहली बार औद्योगिक विकास की रैंकिंग जारी की है, जिसमें औद्योगिक योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर ज़िलों को रैंकिंग प्रदान की गई है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य में औद्योगिक विकास की इस रैंकिंग में सिवान (73.5 अंक) पहले और पटना (68 अंक) दूसरे स्थान पर है।
- इसके अलावा मुंगेर, शेखपुरा, सहरसा, किशनगंज, बक्सर, बेगूसराय, नालंदा और कैमूर ज़िलों को भी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये प्रथम 10 ज़िलों में रखा गया है। अंतिम पायदान पर रहने वाले पाँच ज़िलों में बांका, सुपौल, गया, मधेपुरा और कटिहार शामिल हैं।
- संदीप पौंडरीक ने बताया कि ज़िलों की रैंकिंग में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार स्टार्टअप, बैंकों और उद्यमियों के साथ संवाद, एमएसएमइ योजना, पीएमएफएम ई-योजना, पीएमइजीपी योजना आदि के क्रियान्वयन में ज़िलों द्वारा किये गए प्रयासों के आधार पर ज़िलावार रैंकिंग तैयार की गई है।

देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में पाँचों बिहार के

चर्चा में क्यों ?

14 दिसंबर, 2022 को केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से जारी आँकड़ों के मुताबिक देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शीर्ष पाँच शहरों में पांचों बिहार के हैं। इसमें देश भर में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर पूर्णिया है, जिसका एक्यूआई 450 दर्ज किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- आँकड़ों के मुताबिक पूर्णिया के बाद देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर दरभंगा रहा है जहाँ एक्यूआई 446 रहा है। तीसरे स्थान पर बेतिया है जिसका एक्यूआई 439 रहा। 421 एक्यूआई के साथ बेगूसराय चौथे और 420 एक्यूआई वाला कटिहार देश का पाँचवा सबसे प्रदूषित शहर रहा है।
- आँकड़ों के मुताबिक पटना का एक्यूआई 347 रहा है। यहाँ प्रदूषण खतरनाक स्तर से नीचे आकर बेहद खराब स्तर तक आ गया है।
- इसके साथ ही राज्य का अररिया, भागलपुर, बिहारशरीफ, छपरा, किशनगंज, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर, सीवान का एक्यूआई 300 से अधिक रहा है। इस तरह से इन शहरों की हवा बेहद खराब स्तर पर पहुँच गई है।
- गौरतलब है कि 400 से ज्यादा एक्यूआई प्रदूषण का खतरनाक स्तर माना जाता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिये बेहद खतरनाक होता है।

पटना में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने का काम शुरू

चर्चा में क्यों ?

14 दिसंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार पटना जंक्शन के पास स्मार्ट सिटी की एक महत्त्वाकांक्षी योजना मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने का काम शुरू हो गया है। योजना के तहत इस पर लगभग 67 करोड़ खर्च होंगे।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार पटना जंक्शन के पास बकरी बाज़ार वाली जगह पर लगभग 38 एकड़ में ट्रांसपोर्ट हब बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। यहाँ अंडरग्राउंड, ग्राउंड, फस्ट और सेंकेंड फ्लोर मिलाकर कुल चार फ्लोर में लगभग 296 वाहनों को लगाने की क्षमता रहेगी।
- स्मार्ट सिटी के इस प्रोजेक्ट को भवन निर्माण निगम की ओर से बनाने का काम शुरू किया गया है। गोविंदा कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी इस प्रोजेक्ट को तैयार करेगी। कंपनी को जून 2023 में ही इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है।
- गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से स्मार्ट सिटी की सभी योजनाओं को अगले वर्ष जून तक पूरा करने के निर्देश दिये गए हैं, इसलिये सभी प्रोजेक्टों पर तेजी से काम पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

नोट :

- मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब से पटना जंक्शन पहुँचने के लिये 440 मीटर सब-वे का निर्माण किया जा रहा है। इसमें 340 मीटर भूमिगत रहेगा। सब-वे में एस्केलेटर, ट्रैवलेटर और वॉकवे, अग्निशामक, लाइट, एलइडी स्क्रीन और ड्रेनेज सिस्टम होंगे। इससे लोग सीधे जंक्शन परिसर (पुराना दूध मार्केट) निकल जाएंगे।

बिहार नगर पालिका विधेयक, 2022 पारित

चर्चा में क्यों ?

15 दिसंबर, 2022 को पटना विधानसभा में हंगामे के बीच बिहार नगर पालिका विधेयक, 2022 पारित हो गया। इसके तहत सार्वजनिक भूमि को गिराने से पहले स्थानीय निकायों को अतिक्रमणकारियों को पहले सूचना देनी होगी।

प्रमुख बिंदु

- सारण जहरीली त्रासदी को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच सदन में यह विधेयक पारित हो गया। विधेयक के अनुसार, निकाय अधिकारी नोटिस जारी करने के 24 घंटे बाद अस्थायी अतिक्रमण और 15 दिन की नोटिस अवधि के बाद ही स्थायी अतिक्रमण हटा सकते हैं।
- उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य सरकार झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने के लिये एक पुनर्वास नीति लेकर आ रही है। प्रारंभिक सर्वेक्षण के अनुसार, सरकार उन 48,000 प्रभावित झुग्गी-झोपड़ियों के पुनर्वास की तैयारी कर रही है, जिनके घर पटना में हाल के अभियानों के दौरान ध्वस्त कर दिये गए थे।
- इसके साथ ही विधानसभा ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग विधेयक, 2022 भी पारित कर दिया है।

बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब 611 प्रकार की दवाएँ मुफ्त में मिलेगी, बिहार सरकार ने जारी की गाइड लाइन

चर्चा में क्यों ?

16 दिसंबर, 2022 को बिहार सरकार ने सरकारी अस्पतालों में दवाओं के वितरण को लेकर नया गाइडलाइन जारी किया है। नये नियम के मुताबिक अब सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को 611 प्रकार की दवाएँ मुफ्त में मिलेंगी।

प्रमुख बिंदु

- नयी-नयी बीमारियाँ सामने आने के बाद सरकार ने सरकारी अस्पतालों में दवाओं के वितरण को लेकर नया गाइडलाइन जारी किया है। इसके तहत अब मरीजों को निजी दुकानों से दवा नहीं खरीदनी पड़ेगी।
- सरकार की ओर से जारी नये संकल्प में मेडिकल कॉलेज से लेकर ज़िला अस्पताल व स्वास्थ्य उपकेंद्र तक के अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी में कुल 611 प्रकार की दवाओं के वितरण करने का निर्णय लिया गया है।
- बिहार के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी-
  - मेडिकल कॉलेज: ओपीडी-356, आईपीडी-256
  - ज़िला अस्पताल: ओपीडी-287, आईपीडी-169
  - अनुमंडलीय अस्पताल: ओपीडी-212, आईपीडी-101
  - सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र: ओपीडी-212, आईपीडी-97
  - रेफरल अस्पताल: ओपीडी-203, आईपीडी-98
  - प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र: ओपीडी-201, आईपीडी-93
  - शहरी पीएचसी: ओपीडी-180
  - अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र: ओपीडी-140, आईपीडी-53

नोट :

- हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर: ओपीडी-151
- स्वास्थ्य उपकेंद्र टेलीमेडिसीन: ओपीडी-97
- स्वास्थ्य उपकेंद्र एल1: ओपीडी-72
- स्वास्थ्य उपकेंद्र: ओपीडी-32

- मानसिक विज्ञान केंद्र कोइलवर: ओपीडी-144

पटना में मनाया जाएगा 13वाँ फिल्मोत्सव

चर्चा में क्यों ?

16 दिसंबर, 2022 को छज्जूबाग में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ साहित्यकार यादवेंद्र, फिल्मोत्सव की संयोजक प्रीति प्रभा और हिरावल के संयोजक संतोष झा ने बताया कि 13वाँ पटना फिल्मोत्सव 19 दिसंबर से 21 दिसंबर तक पटना में मनाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- कालिदास रंगालय में आयोजित होने वाले इस फिल्मोत्सव में एक दर्जन फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिन्हें दर्शक नि:शुल्क देख सकेंगे।
- फिल्मोत्सव में मुंबई, केरल, कोलकाता, दिल्ली, अलीगढ़ और राँची से कुल आठ फिल्मकार अपनी फिल्मों के साथ आ रहे हैं। एक सेक्शन स्थानीय युवा फिल्मकारों का भी होगा।
- 13वें फिल्मोत्सव का उद्घाटन हिन्दी के वरिष्ठ कवि और आईआईटी, हैदराबाद में प्रोफेसर हरजिंदर सिंह लाल्टू करेंगे। पहले दिन दो साहित्यिक कृतियों पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिनमें संवदिया (फणीश्वर नाथ रेणु) और लौट रही है बेला एक्का (अरुण प्रकाश) शामिल हैं। फिल्म के प्रदर्शन के बाद उपस्थित निर्देशकों के साथ दर्शकों के संवाद का भी सत्र होगा।
- फिल्मोत्सव में दिखाई जानेवाली आखिरी फिल्म ''मट्टो की साइकिल' होगी। जाने-माने फिल्म निर्देशक प्रकाश झा ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म का प्रीमियर बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। इसके निर्देशक मो. गनी भी फिल्मोत्सव में शिरकत करेंगे।

बिहार का हरित बजट पिछले साल की तुलना में 3.26 फीसदी हुआ कम

चर्चा में क्यों ?

16 दिसंबर, 2022 को बिहार का तीसरा वित्तीय वर्ष 2022-23 का हरित बजट शीतकालीन सत्र में पेश किया गया। पिछले वर्षों की तुलना में हरित बजट में 3.26 फीसदी की कमी आई है।

प्रमुख बिंदु

- हरित बजट के अंतर्गत चिह्नित विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों पर बजट आवंटन में कमी आई है। वर्ष 2021-22 में बजट 79359 करोड़ रुपए था, जो 2022-23 में घटकर 79255 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि कार्यक्रमों का कुल बजट आवंटन भी 29337 करोड़ रुपए से कम होकर 28380 करोड़ रुपए हो गया।
- गौरतलब है कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है, जो हरित बजट पेश करता रहा है। इससे विभागों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिये चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद मिलती है। इस बजट की मदद से पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बजटीय प्रावधानों का अध्ययन एवं आकलन किया जाता है।
- राज्य सरकार जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए इस बजट पर फोकस कर रही है। बिहार देश के उन गिने-चुने राज्यों में से एक है, जो जलवायु परिवर्तन के हिसाब से कृषि को भी बढ़ावा दे रहे हैं।
- हरित बजट में स्कीम मदों में सर्वाधिक आवंटन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में इस विभाग में स्कीम मद का आवंटन 663 करोड़ रुपए में से हरित योजनाओं के लिये 655 करोड़ रुपए आरक्षित किया गया है। यह कुल स्कीम मद का 98.74 फीसदी है।

नोट :

- इस मामले में गन्ना उद्योग विभाग दूसरे स्थान पर है। विभाग में स्कीम मद का आवंटन 100 करोड़ रुपए था, जिसमें 98.70 करोड़ रुपए हरित योजनाओं के लिये आवंटित किये गए। वहीं, तीसरे स्थान पर लघु जल संसाधन है, जिसके स्कीम मद का कुल आवंटन 827 करोड़ रुपए में से हरित योजनाओं के लिये 796 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है।

बिहार को मिलेगी एक नए एक्सप्रेस-वे की सौगात, 2023 में शुरू होगा रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस-वे का निर्माण

चर्चा में क्यों ?

18 दिसंबर, 2022 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार को जल्द ही एक नए एक्सप्रेस-वे की सौगात मिलने जा रही है। प्रदेश के रक्सौल से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिये डीपीआर तैयार की जा रही है। एक्सप्रेस-वे का निर्माण 2023 में शुरू होगा।

प्रमुख बिंदु

- सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब 695 किमी. लंबाई में रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस-वे के निर्माण में करीब 54 हज़ार करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके साथ ही इस सड़क को पूरा करने की समय-सीमा 2025 तय की गई है।
- गौरतलब है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नेपाल पोर्ट से पश्चिम बंगाल के हल्दिया पोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिये रक्सौल से हल्दिया एक्सप्रेस-वे की स्वीकृति दी है। इस सड़क के बन जाने से देवघर से काठमांडू की दूरी महज़ 12 घंटे में पूरी की जा सकेगी।
- रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस-वे बिहार के कई ज़िलों से होकर झारखंड व पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक पहुँचेगा। इस दौरान यह राज्य के करीब नौ ज़िलों से होकर गुज़रेगा। इनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुज़फ्फरपुर, सारण, पटना, बिहारशरीफ, शेखपुरा, जमुई और बाँका शामिल हैं। इसके बाद यह एक्सप्रेस-वे झारखंड में प्रवेश कर सरैयाहाट, नोनीहाट व दुमका से पश्चिम बंगाल के पानागढ़ से हल्दिया पोर्ट चला जाएगा।
- दरअसल नेपाल के लिये भारत के अलावा ज़्यादातर माल अन्य देशों से आता है, लेकिन नेपाल जाने के लिये माल हल्दिया सी-पोर्ट पर ही उतरता है। हल्दिया पोर्ट पर जहाज़ से माल उतरता है और ट्रक व ट्रेन के माध्यम से रक्सौल के सिरिसिया स्थित ड्राइपोर्ट पहुँचता है। यहाँ से माल की डिलिवरी रक्सौल व भारत के नज़दीकी शहरों में होती है। वहीं, नेपाल में आने वाला माल रक्सौल ड्राइपोर्ट से झारखंड व पश्चिम बंगाल के लिये भेजा जाता है। नया एक्सप्रेस-वे बनने से माल भेजने में भी सुविधा मिलेगी।

स्वच्छता सर्वे 2023 के तहत ब्रांडिंग में प्लास्टिक का बैनर-पोस्टर लगाने पर कटेंगे 25 अंक

चर्चा में क्यों ?

19 दिसंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार स्वच्छ सर्वेक्षण-2023 में बेहतर रैंकिंग पाने के लिये बिहार के सभी नगर निकायों को डिजिटल तरीके से ज्यादा प्रचार-प्रसार करने होंगे क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और स्वच्छ सर्वेक्षण में अगर किसी भी स्थिति में ब्रांडिंग के लिये फ्लेक्स, पॉलिथिन या प्लास्टिक का उपयोग किया जाएगा तो सीधे 25 अंकों की कटौती हो जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार, प्लास्टिक वाला फ्लैक्स व बैनर लगाने पर रैंकिंग बिगड़ जाएगी। इसके लिये मंत्रालय ने राज्य के सभी नगर निकायों को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।
- इसके बाद स्थानीय स्तर पर, मुजफ्फरपुर नगर निगम ने बैनर व फ्लैक्स की बजाय शहर में जगह-जगह स्मार्ट सिटी से लगे एलइडी स्क्रीन के माध्यम से स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक करते हुए संदेश देना शुरू कर दिया है। इसकी कार्य योजना तैयार कर सर्वेक्षण को केंद्र सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

नोट :

- इस बार पूरे प्रतियोगिता के दौरान कलाकृतियाँ एवं स्लोगन (आर्ट वर्क) पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। थीम के अनुरूप ही इस बार 48 प्रतिशत यानी 4525 अंक अकेले सर्विस लेवल प्रोग्राम यानी कूड़े को लेकर सेग्रीग्रेशन, प्रोसेसिंग व डिस्पोजल पर आधारित रहेंगे। 27 प्रतिशत यानी 2500 अंक सर्टिफिकेशन के होंगे और 25 प्रतिशत यानी 2475 अंक सिटीजन वॉइस के होंगे।
- वार्डों को ऐसे मिलेंगे अंक -
  - वार्डों में 95 प्रतिशत से अधिक व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर 25 अंक।
  - वार्डों में 75 से 90 प्रतिशत तक प्रचार-प्रसार करने पर 20 अंक।
  - वार्डों में 50 से 74 प्रतिशत तक प्रचार-प्रसार करने पर 15 अंक।
  - वार्डों में 50 प्रतिशत से कम प्रचार-प्रसार करने पर 10 अंक।

बागमती बांध के किनारे बनेगा बेनीपुरी का स्मारक

चर्चा में क्यों ?

20 दिसंबर, 2022 को बिहार के मुजफ्फरपुर के बेनीपुरी चेतना समिति न्यास के सचिव डॉ. महंथ राजीव रंजन दास ने बताया कि बागमती बांध के किनारे बिहार सरकार की ओर से आवंटित ज़मीन पर रामवृक्ष बेनीपुरी के स्मारक निर्माण के प्रस्ताव को सरकार ने मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- डॉ. महंथ राजीव रंजन दास ने बताया कि बागमती बांध के किनारे बनने वाले रामवृक्ष बेनीपुरी स्मारक के निर्माण पर 13 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बागमती बांध के बाहर 1.4 एकड़ और 14 डिसमिल ज़मीन आवंटित है। स्मारक परिसर में उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित होगी।
- उन्होंने बताया कि इस स्मारक के साथ-साथ चहारदिवारी, पार्क, वाचनालय व पुस्तकालय और मेन गेट का निर्माण भी प्रस्तावित है।
- ज्ञातव्य है कि बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर इस स्मारक के लिये लगातार प्रयास कर रहे थे। उनके प्रयास से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्मारक निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
- विदित है कि रामवृक्ष बेनीपुरी मुजफ्फरपुर समाजवादी आंदोलन के जनक, स्वतंत्रता सेनानी व प्रख्यात लेखक थे।
- उल्लेखनीय है कि बागमती नदी हिमालय की महाभारत श्रेणियों में नेपाल से निकलती है। यह नदी नेपाल में लगभग 195 किलोमीटर की यात्रा तय करके भारत में बिहार के सीतामढ़ी ज़िले में प्रवेश करती है। बिहार में इस नदी की कुल लंबाई 394 किलोमीटर है। नेपाल में इस नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र 7884 वर्ग किलोमीटर है।

बिहार की शालिनी कुमारी को तीसरे आसियान-भारत ग्रासरूट इनोवेशन फोरम में उनके नवाचार 'मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग्स' के लिये मिला प्रथम पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

21 दिसंबर, 2022 को बिहार की शालिनी कुमारी को तीसरे आसियान-भारत ग्रासरूट इनोवेशन फोरम में जमीनी स्तर की नवोन्मेष प्रतियोगिता (ग्रासरूट इनोवेशन कम्पटीशन) में उनके नवाचार 'मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग्स'के लिये प्रथम पुरस्कार मिला।

प्रमुख बिंदु

- शालिनी कुमारी ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष पर समिति (सीओएसटीआई) कंबोडिया के अध्यक्ष और किंगडम ऑफ कंबोडिया में उद्योग विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रालय (एमआईएसटीआई) के महानिदेशक महामहिम डॉ. हुल सिंघेंग, के तहत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार विभाग के जनरल विभाग से यह पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने प्रथम पुरस्कार की विजेता होने के कारण 1,500 अमेरिकी डॉलर का नकद पुरस्कार जीता।
- दूसरा और तीसरा पुरस्कार क्रमश: फिलीपींस और म्यांमार के ज़मीनी नवप्रवर्तकों द्वारा जीता गया, जिन्होंने क्रमश: 1000 अमेरिकी डॉलर और 500 अमेरिकी डॉलर जीते। ज़मीनी स्तर के कुल 45 नवप्रवर्तकों ने भाग लिया और इस प्रतियोगिता में 9 देशों का प्रतिनिधित्व किया।

नोट :

- स्टूडेंट इनोवेशन प्रतियोगिता में पहला और दूसरा पुरस्कार थाईलैंड के प्रतिभागियों ने जीता, जबकि तीसरा पुरस्कार लाओ पीडीआर के छात्र ने जीता। 9 देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए कुल 37 प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया था।
- प्रथम पुरस्कार विजेता शालिनी कुमारी, पटना की निवासी हैं। उन्हें पहली बार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त निकाय नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा अपनी तकनीक के लिये वर्ष 2011 में इग्नाईट (आईजीएनआईटीई) प्रतियोगिता के माध्यम से मान्यता दी गई थी।
- उल्लेखनीय है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (एनआईएफ) के साथ साझेदारी में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (सीओएसटीआई) पर दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान (एएसईएएन) की समिति द्वारा नोम पेन्ह, कंबोडिया में 19-21 दिसंबर तक तीसरे आसियान भारत ग्रासरूट इनोवेशन फोरम का आयोजन किया गया।
- इस फोरम में ग्रासरूट इनोवेशन प्रतियोगिता, छात्र नवाचार प्रतियोगिता,पैनल चर्चा, मुख्य भाषण और नवाचारों की एक प्रदर्शनी शामिल थी जिसमें भारत और आसियान सदस्य राज्यों (एएमएस) के प्रतिभागी शामिल थे।
- तीसरे आसियान-भारत ग्रासरूट इनोवेशन फोरम के साथ-साथ कंबोडिया में दूसरी सरकार की बैठक भी आयोजित की गई जिसमें आसियान सदस्य देशों, भारत और आसियान सचिवालय के प्रतिनिधि शामिल थे।
- गौरतलब है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के साथ साझेदारी में आसियान इंडिया ग्रासरूट इनोवेशन फोरम सालाना सीओइटीआई का आयोजन करता है, जिसमें सम्मेलन सत्र, इनोवेशन प्रतियोगिताएँ और एक प्रदर्शनी शामिल है। प्रमुख प्रतिभागियों अर्थात् सरकारी अधिकारियों, ज़मीनी नवोन्मेषकों, छात्र नवप्रवर्तकों, शिक्षाविदों, व्यावसायिक अभिनेताओं और व्यापक समुदाय को एक साथ लाकर यह मंच ज़मीनी स्तर पर नवोन्मेष/नवाचार इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा देने तथा मज़बूत करने के लिये एक स्थान प्रदान करता है।
- पहले दो मंच क्रमश: इंडोनेशिया (2018) और फिलीपींस (2019) में आयोजित किये गए थे, जबकि महामारी के कारण दो साल का संक्षिप्त विराम था।

बिहार में शिक्षक नियोजन के नियमों में होगा बड़ा बदलाव

चर्चा में क्यों ?

22 दिसंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में शिक्षक नियोजन के संदर्भ में सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की नियमावली में बड़ा बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। प्राथमिक चरण से उच्च माध्यमिक स्तर तक के शिक्षकों के नियोजन के लिये एक ही नियमावली तैयारी की गई है। इससे पहले नियमावली अलग-अलग हुआ करती थी।

प्रमुख बिंदु

- राज्य में शिक्षक नियोजन के नियमों में बदलाव के अंतर्गत इस बार विभिन्न वर्गों के ढाई लाख से अधिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर पंचायती राज संस्थाएँ बहाली नहीं करेंगी। राज्य सरकार शिक्षक चयन प्रक्रिया से पंचायती राज की भूमिका को हटाने जा रही है।
- शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिये ज़िला स्तर पर केंद्रीकृत इकाई गठित की जाएंगी। यही संस्था शिक्षक पद के लिये अनुशंसित अभ्यर्थियों की न केवल ज़िला स्तर पर कांउसलिंग करेगी, बल्कि उन्हें नियुक्ति पत्र भी बाँटेगी। पंचायत से लेकर प्रखंड और नगरीय निकायों के दायरे में आने वाले सभी चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र ज़िला मुख्यालय से ही बाँटे जाएंगे।
- उपरोक्त सारे तथ्य सातवें चरण के शिक्षक नियोजन के लिये तैयार की जा रही नियमावली में प्रस्तावित किये गए हैं। नियमावली को राज्य सरकार के शीर्ष अफसरों की राय के लिये भेजा गया है तथा शीर्ष अफसरों की राय को विभागीय अफसरों की नियमावली बनाने वाली समिति समाहित कर उसे अंतिम रूप देकर कैबिनेट को भेजेगी।
- चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार नहीं होगा। हालाँकि चयन करने वाली एजेंसी के लिये तीन विकल्प सुझाए गए हैं। इसके लिये बिहार लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग तथा बिहार तकनीकी सेवा आयोग में से किसी एक एंजेंसी का चयन किया जाना है।
- इस बार प्राथमिक, माध्य, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालयाध्यक्ष, कंप्यूटर शिक्षक सहित सभी की वेकेंसी एक साथ निकाली जाएगी। इनकी नियुक्ति का शेड्यूल एक ही समयावधि में रहेगा। नियुक्ति च्वाइस के आधार पर की जाएगी। सभी को ज़िला संवर्ग में रखा जाएगा।

नोट :

बिहार के 16 शहरों में 1136 करोड़ की लागत से एसटीपी व ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाएंगे

चर्चा में क्यों ?

23 दिसंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के 16 शहरों में जलजमाव व गंदे पानी की निकासी को लेकर 1136 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) व ड्रेनेज निर्माण को लेकर योजना तैयार की गई है। इन योजनाओं का विस्तृत प्लान (डीपीआर) तैयार कर राज्य व केंद्र सरकार को मंज़ूरी के लिये भेजा गया है।

प्रमुख बिंदु

- शहरों की ज़रूरत को देखते हुए ड्रेनेज नेटवर्क और एसटीपी की योजनाएँ तैयार की गई हैं। डीपीआर के मुताबिक किशनगंज, रक्सौल और मोतीहारी शहर में अलग-अलग क्षमता के तीन-2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे, वहीं जमुई, सहरसा और दरभंगा में दो-दो एसटीपी लगाए जाएंगे।
- स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप (एसपीएमजी) और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की मंज़ूरी मिलते ही विधिवत रूप से टेंडर प्रक्रिया व एजेंसी का चयन कर काम शुरू कर दिया जाएगा।
- इसके अलावा राज्य के पाँच शहरों आरा, बेतिया, कटिहार, जमालपुर, जोगबनी में सीवरेज नेटवर्क और एसटीपी के लिये डीपीआर निर्माण की प्रक्रिया चल रही है।
- आधिकारिक जानकारी के मुताबिक राज्य के 16 में से 3 शहरों दिघवारा, मनिहारी और तेघड़ा में फीकल सल्ज ट्रीटमेंट प्लांट (मानव मल प्रबंधन) पर काम होगा। इस प्लांट के ज़रिये शौचालय टैंक के गाद से जैविक खाद बनाई जाएगी।
- ट्रीटमेंट प्लांट से यहाँ आने वाली गंदगी को निस्तारित कर खाद बनाया जाएगा व पानी को साफ कर दूसरे प्रयोगों में लाया जाएगा।
- विदित है कि वर्तमान में राज्य में सेप्टिक टैंक के गाद को टैकों में भरकर खुले में सड़क के किनारे गिरा दिया जाता है, जिससे पर्यावरण प्रदुषित होता है।

बिहार की कोसी-मेची लिंक परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ

चर्चा में क्यों ?

25 दिसंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार की अति महत्त्वाकांक्षी कोसी-मेची लिंक परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इस परियोजना का डीपीआर बनाने के लिये जल संसाधन विभाग और केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन विभाग की नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- कोसी-मेची लिंक परियोजना के पूरा होने पर राज्य के सीमांचल के चार ज़िलों में करीब 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा और बाढ़ से राहत मिलेगी। इनमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया ज़िला शामिल हैं।
- इस परियोजना से अररिया ज़िले में करीब 69 हज़ार हेक्टेयर, पूर्णिया ज़िले में करीब 69 हज़ार हेक्टेयर, किशनगंज ज़िले में 39 हज़ार हेक्टेयर और कटिहार ज़िले में 35 हज़ार हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई होगी।
- कोसी-मेची लिंक परियोजना से अररिया ज़िले के अंतर्गत फारबिसगंज, कुर्साकाटा, सिकटी, पलासी, जोकीहाट एवं अररिया प्रखंड को लाभ होगा। वहीं, किशनगंज ज़िले के अंतर्गत टेढ़ागाछ, दिघलबैंक, बहादुरगंज एवं कोचाधामन प्रखंड को लाभ होगा।
- इसके अलावा पूर्णिया ज़िले के अंतर्गत बैसा, अमौर एवं बायसी प्रखंड तथा कटिहार ज़िले के अंतर्गत कदवा, डंडखोड़ा, प्राणपुर, मनिहारी एवं अमदाबाद प्रखंड लाभान्वित होंगे।
- विदित है कि कोसी-मेची लिंक परियोजना का काम शुरू करने के लिये पहले ही राज्य कैबिनेट से मंज़ूरी मिल चुकी है। मई 2022 में ही राज्य सरकार ने डीपीआर गठन, सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य के लिये करीब दो करोड़ 78 लाख रुपए की प्रशासनिक और खर्च की स्वीकृति दे दी थी।

नोट :

- राज्य सरकार द्वारा 90 फीसदी केंद्रांश की हो रही मांग तथा केंद्र सरकार द्वारा इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करते हुए, इसके लिये केंद्रांश 60 फीसदी और राज्यांश 40 फीसदी के रूप में बजटीय प्रावधान की मंज़ूरी दी गई है।
- हालांकि, राज्य सरकार की ओर से कोसी-मेची लिंक परियोजना के लिये भी मध्य प्रदेश की केन-बेतवा लिंक परियोजना की तर्ज़ पर केंद्रांश 90 फीसदी और राज्यांश 10 फीसदी बजटीय प्रावधान की मांग जारी है।
- इस परियोजना के अंतर्गत कुल लगभग 1397 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से 632 हेक्टेयर भूमि पूर्व से अधिगृहीत है, जबकि 765 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है।

'नमामि गंगे' में अब भूगर्भ जल को भी साफ करने की योजना

चर्चा में क्यों ?

26 दिसंबर, 2022 को बिहार शहरी अवसंरचना विकास निगम (बुडको) के एमडी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य में नमामि गंगे परियोजना के तहत नदियों के साथ ही भूगर्भ जल को भी स्वच्छ रखने का काम शुरू होगा, जिसके लिये 78 छोटे शहरों का चयन भी कर लिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- बुडको के एमडी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि इस परियोजना के तहत बिहार के 78 छोटे शहरों के नाले का पानी भी साफ होकर नदियों या तालाबों में गिरेगा। इन शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का काम जल्द शुरू होगा।
- विदित है कि राज्य में कई शहरों के नाले का पानी सीधे नदियों में गिराया जा रहा है। कई शहरों में तालाब या निचले भूखंडों में बहा दिया जाता है। दो माह पहले इन छोटे शहरों या निकायों का चयन किया गया है, जिसमें बीस हज़ार से ऊपर की आबादी वाले कुल 138 शहरी निकाय हैं।
- उन्होंने बताया कि वर्तमान में 26 शहरी निकायों में एसटीपी बनकर तैयार है। वहीं 18 शहरों या निकायों में एसटीपी के लिये डीपीआर को स्वीकृति मिल चुकी है। दो निकाय बक्सर और खगड़िया की डीपीआर को संशोधित किया जा रहा है। तीन अन्य निकायों- राजगीर, बोधगया और बिहारशरीफ में भी एसटीपी का काम चल रहा है। ग्यारह नए शहरों में एसटीपी की डीपीआर बनाने के लिये एजेंसियों से आवेदन मांगे गए हैं। इस तरह कुल 60 निकायों या शहरों के लिये एसटीपी बनाने काम या तो हो गया है या फिर प्रक्रिया में है।
- धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि नदी-तालाबों सहित विभिन्न जलस्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखने पर राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। जल-जीवन-हरियाली योजना के अंतर्गत भी इस पर काम हो रहा है। राज्य के छोटे शहरों के गंदे पानी को भी साफ करने के लिये ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का निर्णय लिया गया है।
- उन्होंने बताया कि सरकार ने राज्य के सभी जलस्रोतों का सर्वे कराने का भी निर्णय लिया है ताकि उनका सटीक आँकड़ा मिले व उसके आधार पर योजना बने और इन जलस्रोतों को मछली उत्पादन के लिये विकसित किया जा सके। इससे राज्य का भूजलस्तर तो बेहतर होगा ही, जलस्रोतों का पानी भी साफ-सुथरा रहेगा।
- परियोजना के तहत ज्यादातर छोटे निकायों में एफएसटीपी (फिकल स्लग ट्रीटमेंट प्लांट) यानी अपशिष्ट शोधन संयंत्र लगाया जाएगा। अभी ज्यादातर छोटे शहरों में सेप्टिक टैंक भरने पर उसे नालियों में बहाने या टैंकर के माध्यम से दूसरे स्थानों पर नालों में फेंका जाता है। अब इसका सुरक्षित तरीके से निस्तारण हो सकेगा। इससे भूगर्भ जल प्रदूषण से निजात मिलेगी। साथ ही जैविक खाद और बेकार पानी से खेतों की सिंचाई भी हो सकेगी।

कैमूर में खुलेगा वाटर स्पोर्ट्स सेंटर

चर्चा में क्यों ?

28 दिसंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के कैमूर ज़िले में पर्यटन विकास को लेकर वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की तैयारी हो चुकी है। इसे लेकर भारत सरकार के जलशक्ति मंत्रालय की ओर से कैमूर ज़िला प्रशासन को पानी के खेलों के लिये सेंटर बनाने के लिये उपयुक्त बाँध स्थल या चौड़ी नदी के पाट या बड़े घाटों को चयनित करने का निर्देश दिया गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- राज्य में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने के संबंध में पानी के खेलों को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार के जलशक्ति मंत्रालय की मांग का हवाला देते हुए राज्य सरकार के स्तर से कैमूर, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर तथा सासाराम ज़िला प्रशासन को पत्र भेजा गया है।
- गौरतलब है कि कैमूर से सटे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राज्य की झीलों में एक रामगढ़ झील में उत्तर प्रदेश सरकार वाटर स्पोर्टस सेंटर का संचालन करा रही है। वहाँ पानी के राज्यस्तरीय और राष्ट्रीयस्तर की प्रतियोगिता आयोजित कराई जाती हैं।
- कैमूर ज़िले में वाटर स्पोर्टस सेंटर का संचालन शुरू कराया जाता है, तो पानी के खेलों के खिलाड़ियों समेत इन सेंटर पर आने वाले पर्यटकों को भी पानी के खेलों का आनंद उठाने का सुनहरा मौका मिलेगा।
- जानकारी के अनुसार, वाटर स्पोर्ट्स सेंटरों पर बोटिंग, वाटर बाइकिंग, स्कीइंग आदि खेल की सुविधाएँ विकसित कराई जाएंगी। इन सेंटरों पर जल क्रीड़ा क्षेत्र के खेल नौका दौड़, तैराकी आदि विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन कराया जा सकेगा।
- इन सुविधाओं के बहाल होने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर वाटर स्पोर्ट्स सेंटर की पहचान कायम हो जाएगी और जल क्षेत्र के स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा तराशने और उच्च स्तर के खिलाड़ियों के साथ अभ्यास करने का सुनहरा अवसर मिल पाएगा।
- कैमूर ज़िले में करकटगढ़, तेलहाड़ कुंड, जगदहवाँ डैम समेत पहाड़ी वादियों में कई ऐसे मनोरम जल क्षेत्र हैं, जहाँ लोग विशेष अवसरों समेत वर्षभर आते-जाते रहे हैं।
- वाटर स्पोर्ट्स सेंटर के लिये दुर्गावती जलाशय परियोजना सबसे अनुकूल स्थल हो सकता है। इस परियोजना का जल संग्रहण क्षेत्र 627 वर्ग किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है।
- कैमूर और रोहतास ज़िले के तीन पहाड़ियों को बाँधकर यह परियोजना तैयार की गई है। वर्तमान में इसके जल क्षेत्र में सैलानियों को बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।
- इसके अलावा, इस परियोजना का जल संग्रहण क्षेत्र अब प्रवासी पक्षियों का भी केंद्र बना है और इसे बर्ड सेंचुरी के रूप में विकसित करने का प्रयास हो रहा है।

डॉ. रत्नेश्वर मिश्र को मिलेगा साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

29 दिसंबर, 2022 को साहित्य अकादमी ने हिन्दी, मैथिली और कोंकणी भाषा में वर्ष 2022 का अनुवाद पुरस्कार प्रदान किये जाने की घोषणा की, जिसमें बिहार के डॉ. रत्नेश्वर मिश्र को चमन नाहल के अंग्रेजी उपन्यास 'आजादी' की मैथिली अनुवाद के लिये मैथिली भाषा का पुरस्कार दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि साहित्य अकादमी के अनुवादकों को पुरस्कार के रूप में एक उत्कीर्ण ताम्रफलक और पचास हजार रुपए की राशि अगले वर्ष एक विशेष समारोह में प्रदान की जाएगी।
- दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी इतिहास विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. रत्नेश्वर मिश्र मूल रूप से पूर्णिया के निवासी हैं और वर्तमान में पटना में रहते हैं। मिथिला के चर्चित इतिहासकारों में शुमार 77 वर्षीय डॉ. मिश्र अक्षर साधना के क्षेत्र में भी गंभीर दखल रखते हैं।
- डॉ. मिश्र की कृतियों में मैथिली में प्रकाशित 'आधुनिक मिथिलाक ऐतिहासिक आयाम' के साथ ही हिन्दी में 'विनोदानंद झा: जीवनवृत्त एवं परिवेश', 'अतुल्य बिहार', अंग्रेजी में 'हिस्ट्री ऑफ पूर्णिया: 1722-1793', 'नाइंटींथ सेंचुरी मिथिला: फिनुक्स सर्वे ऑफ ए विलेज'प्रमुख हैं।
- इसके अलावा डॉ. मिश्र की 'भवभूति', 'हिस्ट्री ऑफ तमिल'तथा 'भारत का इतिहास' पुस्तक के भी मैथिली अनुवाद प्रकाशित हैं। आचार्य सुरेंद्र झा सुमन के मैथिली उपन्यास 'उगनाक दयादवाद'का अंग्रेजी अनुवाद भी उन्होंने किया है।

नोट :